ड्रग कंट्रोलर को हटाया, चार निलंबित

बच्चों की मौत के मामले में सीएम की बड़ी कार्रवाई

सीएम ने अफसरों को तलब कर की उच्च स्तरीय बैठक

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 6 अक्टूबर. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को पूर्व निर्धारित जबलपुर का दौरा रद्द कर परासिया का दौरा किया. यहां कोल्ड्रिफ सिरप से मृत बच्चों के परिजनों से मिलने के लिये परासिया रवाना होने से पहले उन्होंने निवास में आला अफसरों को तलब किया और उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की.

इस दौरान उन्होंने बड़ी कार्रवाई करते हुए ड्रग कंट्रोलर को तत्काल हटाने के निर्देश दिये. इतना ही नहीं औषधि निरीक्षक छिंदवाड़ा गौरव शर्मा, औषधि निरीक्षक जबलपुर शरद कुमार जैन, उप संचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन शोभित कोस्टा को निलंबित कर दिया गया है. राज्य सरकार ने देर शाम इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिये हैं.

बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कड़े तेवर दिखाते हुए कहा कि छिंदवाड़ा प्रकरण में सभी दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी. राज्य सरकार सजग और संवेदनशील है, मानव जीवन की सुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि कोल्ड्रिफ सिरप की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के साथ ही दुकानों में विद्यमान स्टॉक जप्त

किया जाए. छिंदवाड़ा और आसपास के जिलों में जिन परिवारों ने यह दवा ली है, उनके घरों से दवा रिकवर करने के लिए सघन अभियान चलाया जाए. आशा-ऊषा कार्यकर्ताओं के साथ ही सभी शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों का सहयोग लिया जाए. कोल्ड्रिफ सिरप दवा के अलावा पिछले दिनों क्षेत्र में बिकने वाली अन्य दवाओं की प्रभावशीलता का भी आकलन कराया जाए. दवाओं पर जो चेतावनी और सावधानियां लिखी जानी चाहिए, वह लिखी जा रही हैं या नहीं इसकी जांच के लिए अभियान आरंभ किया जाए.

इन नियमों का पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई की जाए. चार वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कॉम्बिनेशन ड्रग नहीं देने की व्यवस्था है, जो डॉक्टर इस व्यवस्था का पालन नहीं कर रहे हैं, उन पर भी कार्यवाही की जाए. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कोल्ड्रिफ सिरप की निर्माता कंपनी पर कार्यवाही के लिए तमिलनाडु राज्य सरकार को घटनाक्रम से अवगत कराने के निर्देश भी दिए.

सर्वे के माध्यम से प्रभावित मरीजों को किया चिन्हित

बैठक में बताया गया कि छिंदवाड़ा से गंभीर प्रकरणों की जानकारी प्राप्त होते ही राज्य स्तर से चिकित्सकों का दल छिंदवाड़ा भेजा गया. नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल और सेंट्रल ड्रग्स स्टेण्डर्ड कंट्रोल आर्गेनाइजेशन का भी जांच में सहयोग लिया गया .आठ मरीजों की जाँच के लिए उनके नमूने पुणे स्थित प्रयोगशाला भेजे गए. साथ ही छिंदवाड़ा से विभिन्न दवाओं के सैम्पल लेकर उनकी जांच कराई गई. छिंदवाड़ा और परासिया के निजी चिकित्सकों, अस्पतालों और केमिस्ट के साथ बैठक कर स्थिति का आंकलन किया गया और उन्हें आवश्यक सावधानियां बरतने के संबंध में सलाह दी गई. छिंदवाड़ा जिले में प्रभावित मरीजों को चिन्हित करने के लिए सर्वे आरंभ किया गया. क्षेत्र से प्राप्त हो रहे इस प्रकार के प्रकरणों को आवश्यकता होने पर आगे के इलाज के लिए शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय नागपुर के लिए रैफर किया गया. जिला प्रशासन द्वारा स्थानीय स्तर पर दवा पर प्रतिबंध लगाया गया तथा अस्पतालों और केमिस्टों के निरीक्षण की प्रक्रिया भी शुरू की गई.

दो राज्यों के ड्रग कंट्रोलर्स को दी सूचना

बैठक में जानकारी दी गई कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया और हिमाचल प्रदेश व तमिलनाडु के ड्रग कंट्रोलर्स को भी इस आशय की सूचना दी गई. तमिलनाडु ड्रग कंट्रोलर से कोल्ड्रिफ सिरप की जांच रिपोर्ट में नमूने अमान्य पाये जाने पर त्वरित कार्यवाही करते हुए सिरप के विक्रय को पूरे प्रदेश में प्रतिबंधित किया गया. साथ ही अधिकांश मरीजों को कोल्ड्रिफ दवा लिखने तथा अपने परिवार के सदस्य के माध्यम से कोल्ड्रिफ दवा की बिक्री कराने वाले डॉक्टर के निलंबन और दवा निर्माता के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने की कार्यवाही की गई.

अपना मेडिकल स्टोर का लायसेंस निरस्त

भोपाल. खाद्य एवं औषधि प्रशासन कार्यालय छिंदवाड़ा द्वारा विभिन्न अनियमितताएं पाए जाने पर जिले के परासिया स्थित अपना मेडिकल स्टोर्स का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है. औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी शरद कुमार जैन ने बताया है कि आदेश के बाद इस मेडिकल स्टोर्स द्वारा अब दवाओं का क्रय-विक्रय पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा. उल्लंघन पर तीन से पांच वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है. अनुज्ञापन अधिकारी जैन ने बताया कि विभिन्न बिंदुओं पर अपना मेडिकल स्टोर्स परासिया का निरीक्षण किया गया, जिसमें औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली 1945 के तहत गंभीर अनियमितताएँ पाई गईं. निरीक्षण के दौरान विक्रय रिकॉर्ड अपूर्ण पाए गए, पंजीकृत फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति में दवाओं का विक्रय किया जा रहा था तथा विक्रय बिल प्रस्तुत नहीं किए गए. इन उल्लंघनों के संबंध में औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, किन्तु नियत अवधि में संचालक द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया.

विशेष टीम करेगी रेत माफियाओं की तलाश

उमरिया. अवैध रेत उत्खनन रोकने के दौरान वनरक्षक पर रेत माफिया द्वारा किया गया प्राणघातक हमला और आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद वन विभाग ने अब अवैध रेत परिवहन में उपयोग किए गए ट्रैक्टरों की तलाश और जब्ती के लिए विशेष टीम बनाई है. एसडीओ कुलदीप त्रिपाठी ने बताया कि चंदिया वन परिक्षेत्र के सलैया रिजर्व फॉरेस्ट में रेत माफिया ने वनरक्षक रमाशंकर चौधरी पर हमला किया था. पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया, अवैध रेत खनन और ट्रैक्टर और ट्रालियां अभी जब्त नहीं. इस कारण वन विभाग ने 3 रेंजर्स और 50 से अधिक कर्मचारियों को शामिल करते हुए सघन तलाशी और जप्ती कार्यवाही के लिए विशेष टीम बनाई है.

सीएम-स्वास्थ्य मंत्री जिम्मेदार : पटवारी

छिंदवाड़ा त्रासदी 'सरकारी हत्या'

विशेष संवाददाता

भोपाल, 6 अक्टूबर. मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने छिंदवाड़ा में जहरीली कफ सिरप से हुई 16 मासूम बच्चों की मौत को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है.

उन्होंने इस हृदयविदारक घटना को सरकारी हत्या बताते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव और स्वास्थ्य मंत्री को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया. पटवारी सोमवार को परासिया पहुंचे, जहां उन्होंने शोकग्रस्त परिवारों से मुलाकात की और उनकी व्यथा साझा की। उन्होंने कहा कि यह दुर्घटना नहीं बल्कि भाजपा सरकार की लापरवाही, भ्रष्टाचार और दवा माफिया से मिलीभगत का परिणाम है।

फव्वारा चौक पर आयोजित एकदिवसीय अनशन में भाग लेते हुए उन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर मासूमों को श्रद्धांजलि अर्पित की। अनशन में सैकड़ों कार्यकर्ता और विधायक सुनील उइके, सोहन वाल्मिक, निलेश उइके सहित अनेक नेता मौजूद रहे। पटवारी ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार डॉक्टरों को बलि का बकरा बना रही है, जबकि असली दोषी दवा निर्माता, वितरक और स्वास्थ्य अधिकारी हैं.

जीवन का वास्तविक अर्थ समाज की सेवा

केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह ने वितरित किए लाभ

भोपाल, 6 अक्टूबर. केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को अपने संसदीय क्षेत्र विदिशा के बिलकिसगंज स्थित कृषि उपज मंडी में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित किसानों और महिलाओं को विभिन्न योजनाओं के लाभ वितरित किए और जनता को संबोधित किया.

इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य शिविर का निरीक्षण किया और विभागीय प्रदर्शिनियों का अवलोकन भी किया. मंत्री चौहान ने कहा कि जीवन का वास्तविक अर्थ जनता और समाज की सेवा में है. उन्होंने सभी माताओं और बहनों

को अपने स्वास्थ्य की जांच करवाने का आह्वान किया और कहा कि अगर कोई बीमारी मिले तो उसका पूर्ण उपचार सुनिश्चित किया जाएगा. महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि 'लाड़ली बहना योजना' और 'लखपति दीदी अभियान' के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं की आमदनी बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है और स्व-सहायता समूहों को इस दिशा में मजबूत माध्यम बनाया जाएगा.

अब तक 19 लाख पक्के मकान दिए जा चुके है

कृषि और गरीब कल्याण से संबंधित योजनाओं पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मध्यप्रदेश में अब तक 19 लाख पक्के मकान दिए जा चुके हैं. सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि कोई गरीब कच्चे घर में न रहे, हर जगह बिजली पहुंचे और हर गरीब को सम्मानजनक जीवन मिले. किसानों के फसल नुकसान की स्थिति में उचित सर्वे कर फसल बीमा योजना का लाभ दिलाया जाएगा. मंत्री चौहान ने स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बड़े लक्ष्य तय किए. उन्होंने कहा कि उनका संकल्प है कि सीहोर जिला पूरी तरह टीबी मुक्त हो. इसके लिए डॉक्टरों की टीम सर्वे कर रही है और मरीजों को मुफ्त दवाई एवं पोषण उपलब्ध कराया जाएगा. अब तक 500 मरीजों की जांच की जा चुकी है, जिनमें 90 गर्भवती महिलाएं भी शामिल हैं.

प्राधिकरण भी करेगा अब सिंहस्थ कार्यों का विकास

- **सिंहस्थ और शहर विकास के मद्देनजर 70 बिंदुओं का बोर्ड बैठक में हुआ समावेश**
- **संभाग आयुक्त आशीष सिंह, कलेक्टर रोशन सिंह, सीईओ संदीप सोनी हुए शामिल**
- **56 दुकान ,होटल हब, प्रतिकल्पा को लेकर अधिकारियों ने लिया निर्णय**

नवभारत न्यूज़

उज्जैन. सोमवार को विकास प्राधिकरण की महत्वपूर्ण बोर्ड बैठक हुई जिसमें संभागआयुक्त और सह यूडीए अध्यक्ष आशीष सिंह, कलेक्टर रोशन कुमार सिंह सीईओ संदीप सोनी से लेकर सभी डायरेक्टर, इंजीनियर और कर्मचारी शामिल हुए. बैठक में 70 से अधिक बिंदुओं को शामिल किया गया.

नवभारत से चर्चा में संभागआयुक्त आशीष सिंह, कलेक्टर रोशन सिंह ने बताया कि सिंहस्थ के तहत कई सारे विभागों और निर्माण एजेंसियों को अलग-अलग जिम्मेदारियां दी गई है. यूडीए सिंहस्थ कार्यों में संलग्न रहेगा. प्रचलित निर्माण कार्यों से लेकर आगामी योजनाओं की रूपरेखा तैयार की गई है. बोर्ड बैठक में कई सारे विषयों पर निर्णय लिए गए हैं.

सिंहस्थ में यूडीए की भूमिका

विकास प्राधिकरण के सीईओ संदीप सोनी ने चर्चा में बताया कि शहर विकास के साथ ही सिंहस्थ 2028 के तहत जो जो जिम्मेदारियां प्राधिकरण को मिली है उन पर निर्णय लेने के लिए बोर्ड बैठक में बिंदुओं का समावेश किया गया । 70 से अधिक बिंदुओं को रखा गया , जिसमें अधिकतर में सहमति प्राप्त हो गई है, जो निर्णय नहीं हो पाए हैं उन

बिंदुओं को अगली बोर्ड बैठक में रखा जाएगा ।सिंहस्थ के तहत यूडीए की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है।

यह 11 सड़क बनाएगा प्राधिकरण

शंकरचार्य चौराहे द्वारा दत्त अखाड़ा, भूखीमाता उजड़खेड़ा हनुमान से उज्जैन बड़नगर रोड, खाकचौक से गढ़कालिका, भतृहरि गुफा तक सीसी रोड, कर्कराज पार्किंग से भूखी माता 4 लेन मार्ग, लालपुल तक 24 मी.चौड़ाई (1020 मी) प्रशांति धाम चौराहा से शनिमंदिर तक 12 मी.चौड़ाई, कार्तिक मेला ग्राउण्ड से नईखेड़ी मार्ग (सिंहस्थ बायपास तक) 24 मी.चौड़ाई मार्ग,शनि मंदिर से जीवनखेड़ी 6 लेन 30 मी.चौड़ाई मार्ग, पीपलीनाका से गढ़ कालिका मंदिर, ओखलेश्वर श्मशान तक 45 मी.चौड़ाई, पीपलीनाका से भैरवगढ़ जेल चौराहा तक 6 लेन 45 मी,तक की सड़क यूडीए बनाएगा.

महाकाल मंदिर सहित अन्य योजना

श्री महाकाल मंदिर और महाकाल लोक के विभिन्न प्रवेश द्वारों पर कास्ट आयरन और एम.एस. फेब्रीकेटेड आर्नामेंट गेट कार्य (सिविल कार्य सहित) की निविदा योजना क्रमांक टीडीएस 05/ (ग्राम निमनावासा एवं धतरांवदा) कुल रकबा 80 .29 है. योजना क्रमांक टीडीएस-06 (ग्राम लालपुर एवं धतरांवदा) कुल रकबा 80 .282 है., के विकास की प्रशासकीय स्वीकृति मांगी गई. योजना क्रमांक टीडीएस 3 व टीडीएस-04 के विकास कार्य द्वितीय फेज की निविदा स्वीकृति मांगी गई.

चौड़ीकरण और अन्य निर्माण

क्षिप्रा नदी के पश्चिम भाग पर प्रस्तावित एम.आर.22, 30 मी.चौड़ाई रोड निर्माण कार्य, जूना सोमवारिया से पीपलीनाका, अंकपात चौराहा तक मार्ग चौड़ीकरण,गोरी कुण्ड से ऋण मुक्तेश्वर तक 12 मी.चौड़ाई, गढ़ कालिका मंदिर से पीर मत्स्येन्द्रनाथ समाधि तक 12 मी. तक का कार्य प्राधिकरण करेगा.

सड़क ,पानी ,बिजली कार्य

स्ट्रीट लाईट योजना एमआर-11 सड़क एवं बस्ती को जोड़ती हुई सड़क पर स्ट्रीट लाईट, हाईमास्ट एवं डेकोरेटिव लाईट, क्षिप्रा विहार योजना आरसीसी नालों, सडकों, ब्रिज, पार्कों की बाउण्ड्रीवाल, पानी की लाईन, सीवर लाईन, रामजनार्दन मंदिर परिसर में आंतरिक कॉलम, शिखर, डोम, बाहरी फसाड एवं मंजुषा स्टोन क्लोर्डिंग कार्य की रिपेयरिंग, कार्य विकास प्राधिकरण द्वारा किए जाएंगे।

नवविवाहिता ने साड़ी का फंदा लगाकर की आत्महत्या

नरसिंहपुर. ठेमी थाना क्षेत्र के सांकल गांव में सोमवार सुबह एक नवविवाहिता ने अपने मायके में साड़ी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली. घटना स्थल से पुलिस को चार पन्नों का सुसाइड नोट मिला है, जिसे जब्त कर लिया गया है. थाना प्रभारी प्रीति मिश्रा ने बताया कि मृतका की पहचान अनुपमा पति दीपेश लोधी (27) के रूप में हुई है, उसका विवाह 20 अप्रैल 2025 को सागर जिले के गौरझामर गांव निवासी दीपेश लोधी के साथ हुआ था. बताया गया है कि ससुराल पक्ष से विवाद के चलते वह पिछले दो माह से मायके में रह रही थी. पुलिस के अनुसार, सुसाइड नोट में मृतका ने ससुराल पक्ष के कुछ लोगों पर आरोप लगाए हैं.

फर्जी शराब चालान घोटाले में ईडी ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार

इंदौर. प्रवर्तन निदेशालय ईडी के इंदौर उप-जोनल कार्यालय ने अंश त्रिवेदी और राजू दशवंत को करोड़ों रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई कथित फर्जी शराब चालान घोटाले की जांच के तहत की गई.

जांच में सामने आया कि दोनों आरोपी इस फर्जीवाड़े के मुख्य साजिशकर्ता हैं. आरोप है कि उन्होंने सरकारी कोष को लगभग 49.42 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया. आरोपियों ने चालानों में हेराफेरी कर राशि और शब्दों के कॉलम में बदलाव किया और इन्हें जिला आबकारी कार्यालयों में

जमा कर झूठा प्रमाण प्रस्तुत किया. इस प्रक्रिया के जरिए उन्हें गैरकानूनी एनओसी और लाइसेंस स्वीकृतियां भी मिल गईं. दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें 8 अक्टूबर 2025 तक ईडी हिरासत में भेज दिया. यह कार्रवाई रावजी पुलिस थाने में दर्ज एफआईआर के आधार पर की थी. जांच अब आगे चल रही है ताकि पूरी साजिश और अन्य संबंधित लोगों का पता लगाया जा सके.

समयबद्ध कार्य और जनता की सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता : विजयवर्गीय

- **नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक**
- **नगरीय विकास की योजनाओं पर महत्वपूर्ण निर्देश, महापौरों से वन-टू-वन चर्चा**

भोपाल. नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सोमवार को मंत्रालय में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की. बैठक में सभी नगर निगमों के महापौर, अपर मुख्य सचिव संजय दुबे, नगरीय प्रशासन आयुक्त संकेत भोंडवे, प्रदेश के सभी नगर निगमों के आयुक्त, संभागीय संयुक्त संचालक तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे.

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बैठक में नगरीय निकायों द्वारा संचालित विभिन्न

योजनाओं और परियोजनाओं की विस्तार से समीक्षा की तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. उन्होंने सभी महापौरों से वन-टू-वन चर्चा की और उनके द्वारा उठाए गए क्षेत्रीय समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए त्वरित समाधान के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों के अनुभव और सुझाव नगरीय विकास की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए उनकी बातों को प्राथमिकता दी जाए. बैठक के समापन पर मंत्री विजयवर्गीय ने स्पष्ट कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाए और शासन की अपेक्षाओं के अनुरूप प्रत्येक कार्य समयबद्ध रूप से पूरा किया जाए .उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जनता की सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए योजनाओं को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू किया जाए. बैठक में आदर्श 30 मीटर चौड़ी एवं 5 किलोमीटर लंबी मॉडल सड़क के निर्माण

प्रधानमंत्री आवास योजना और अधोसंरचना कार्यों की समीक्षा

बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की प्रगति, आवास निर्माण की स्थिति और आगामी पांच वर्षों के अधोसंरचना कार्यों की कार्ययोजना पर चर्चा की गई. मंत्री ने अधिकारियों को लक्ष्य प्राप्ति में तेजी लाने के निर्देश दिए.

कार्य की समीक्षा की गई. मंत्री ने गीता भवन कार्ययोजना सहित सभी नगरीय निकायों को इस दिशा में त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए.

अमृत योजना, नमामि गंगे पर जोर

बैठक में अमृत योजना और नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत शहरी जल आपूर्ति, सीवेज प्रणाली और गंगा स्वच्छता से जुड़े कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई. साथ ही प्रधानमंत्री ई-बस योजना के तहत शहरी परिवहन में ई-बसों की उपलब्धता, संचालन और भविष्य की योजना पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए.

आत्मनिर्भर निकायों की दिशा में पहल

मंत्री विजयवर्गीय ने आत्मनिर्भर निकायों के निर्माण की दिशा में ठोस कदम उठाने के लिए सभी नगर निकायों को कर वसूली, आय वृद्धि, जीआईएस असेसमेंट और ऊर्जा ऑडिट जैसे विषयों पर सक्रियता बढ़ाने के निर्देश दिए. उन्होंने वाहन प्रबंधन प्रणाली में सुधार, ईंधन दक्षता बढ़ाने और नगर निकायों के वाहनों के सही संचालन पर भी बल दिया.

आयोजन राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने 'उड़ान' योजना का किया शुभारंभ

केंद्र की योजनाओं से आएगा सामाजिक परिवर्तन

सागर, 6 अक्टूबर. राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा कि सिकल सेल एनीमिया एक अनुवांशिक रक्त संबंधी बीमारी है, इसके प्रति जागरूकता और समय पर उपचार अत्यंत आवश्यक है. उन्होंने कहा कि इस बीमारी से पीड़ित लोगों को सही चिकित्सा और परामर्श उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है.

राज्यपाल सागर जिले के रहली विकासखंड के ग्राम पंचायत कड़ता में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे. इसी अवसर पर उन्होंने

'उड़ान योजना' का शुभारंभ भी किया. राज्यपाल ने कहा कि आज हम गोंडवाना की वीरांगना रानी दुर्गावती की कर्मभूमि में हैं. लगभग पांच सौ वर्षों के बाद भी उनके संघर्ष, वीरता और बलिदान से हम प्रेरणा लेते हैं. उन्होंने कहा कि जनजातीय समाज के वीर सपूत रानी दुर्गावती, राजा शंकरशाह और राजा रघुनाथ शाह देश की सुरक्षा और स्वाभिमान के प्रतीक हैं. इन वीरों के बलिदान को सदैव स्मरण रखना चाहिए.

राज्यपाल ने प्रधानमंत्री उज्जवला योजना, जनमन योजना और धरती आबा उत्कृष्ट ग्राम योजना की भी सराहना की और कहा कि इन योजनाओं से जनजातीय समुदाय में आर्थिक व सामाजिक परिवर्तन आएगा. उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगभग 3 लाख कर्मयोगियों को प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया है.

महिलाओं को मिलेगा रोजगार

राज्यपाल पटेल ने सागर जिले में शुरू की गई फूड फॉरेस्ट योजना को अभिनव पहल बताते हुए कहा कि इस योजना से स्वसहायता समूहों की महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण का अवसर मिलेगा. उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत तीन वर्षों में लगभग 10 लाख पौधे रोपे जाएंगे, जिससे भविष्य में ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्राप्त होंगे. उन्होंने इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक प्रभावी कदम बताया.

राज्यपाल ने कहा कि गोंडी पेंटिंग्स आज देश-विदेश में लोकप्रिय हैं, इन्हें और प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि जनजातीय लोक कलाकारों की कला में अद्भुत भावनात्मक गहराई और परंपरागत पहचान छिपी हुई है. उन्होंने क्षय रोग (टीबी) के प्रति भी लोगों को जागरूक करने की बात कही. राज्यपाल ने कहा कि टीबी रोगियों का निरंतर उपचार और नियमित दवा सेवन सुनिश्चित किया जाना चाहिए.

कसौटी पर रहेंगे कलेक्टर्स-कमिश्नर्स

कॉन्फ्रेंस में अफसरों को सरकार की प्राथमिकताएं गिनाई जाएंगी

02 दिनी कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस आज से

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 6 अक्टूबर. राजधानी में मंगलवार 7 अक्टूबर से दो दिन तक प्रदेश के आला मैदानी अफसरों का जमावड़ा होगा. डॉ. मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार राजधानी में कलेक्टर-कमिश्नर्स कॉन्फ्रेंस होगी.

7 अक्टूबर से शुरू हो रही कॉन्फ्रेंस के लिये अफसरों के राजधानी पहुंचने का सिलसिला सोमवार से ही शुरू हो गया था. कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले मैदानी अफसरों को सरकार की प्राथमिकताएं गिनाई जाएंगी, उसके बाद विभागवार और जिलेवार परफॉर्मेंस को लेकर कलेक्टर सरकार की कसौटी पर रहेंगे. इधर कुशाभाऊ ठाकरे इन्टरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, भोपाल होने वाली कॉन्फ्रेंस के लिये तैयारियां पूरी कर ली गई है. सोमवार को ही राज्य सरकार ने बैठक की व्यवस्था के लिए अपर सचिव सामान्य प्रशासन सुभाष कुमार द्विवेदी, उप सचिव डॉ शैलेन्द्र हिनौतिया, दिलीप कापसे, जयेन्द्र कुमार विजयवत एवं अवर सचिव मनोज श्रीवास्तव को दायित्व सौंपे गये हैं. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शुरुआत में आला मैदानी अफसरों को संबोधित करेंगे और विजन-2047 पर अपना नजरिया रखेंगे. जिससे कि मप्र को विकसित मप्र बनाया जा सके.

दो दिनी कॉन्फ्रेंस के लिये विषयवार अलग- अलग 8 समूह बनाये गये हैं, जिसकी अगुवाई अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी कर रहे हैं. समूह या सेक्टर के लीडर को अपने विषय पर प्रजेंटेशन देने के लिये 20 मिनट का समय तय किया गया है. ये लीडर अपने समूह से संबंधित विषयों को लेकर राज्य सरकार की प्राथमिकता से आला मैदानी अफसरों को रूबरू कराएंगे.

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्रा. लि. हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशुतोष उपाध्याय द्वारा 6/54, फिरोज गांधी प्रेस काम्प्लेक्स, इंदौर से प्रकाशित एवं नवभारत प्रेस भोपाल प्रा.लि. , फिरोज गांधी प्रेस कॉम्प्लेक्स इंदौर से मुद्रित. समूह संपादक क्रांति चतुर्वेदी*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन/फैक्स- 4096718 RNI Reg. No.7590/60